हिमाचल प्रदेश विधान सभा

11.00 पूर्वाह्न

राष्ट्रगान गाया गया।

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ असतो मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्माऽमृतं गमय।
ॐ शान्तिः ॥

माननीय श्रीमान अध्यक्ष व माननीय सदस्यगण

1. मुझे सम्मानीय सदन के इस वर्ष के प्रथम सत्र तथा 12वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 14वें सत्र को सम्बोधित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।

2. मेरी सरकार गत चार वर्षों से प्रदेशवासियों की उन्नति, खुशहाली व समृद्धि के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही है तथा प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया है। मेरी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र, जो हमारे लिए एक नीति दस्तावेज है, में किए गए सभी

वायदों को पूरा किया है। मेरी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित शानदार उपलब्धियां सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की साक्षी हैं।

3. सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति वचनबद्ध है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि विकास के समुचित लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिले। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 'सबका कल्याण-समग्र विकास' के सिद्धांत का सरकार के सभी प्रयासों में अक्षरशः अनुसरण किया जाए।

4. मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा की पहुंच तथा निष्पक्षता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों का ही फल है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त परिषद ने 14 राजकीय महाविद्यालयों को प्रत्यायित किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार ने 154 माध्यमिक स्कूलों तथा 109 राजकीय उच्च पाठशालाओं को क्रमशः उच्च पाठशालाओं व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत किया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 17 नये राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं।

5. नये कॉलेज भवनों के निर्माण पर 40 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं जबकि उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के भवनों के निर्माण पर

39 करोड़ 19 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 1 लाख 41 हजार 724 पात्र विद्यार्थियों को 82 करोड़ 40 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं।

6. मेरी सरकार नौंवी तथा दसवीं कक्षा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग/आईआरडीपी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठय पुस्तकें प्रदान करने पर 9 करोड़ 69 लाख रुपये व्यय कर रही है, जिससे 1 लाख 04 हजार तथा 221 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री वर्दी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 11वीं तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दो जो़डे वर्दी प्रदान करने पर 11 करोड़ 73 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी वर्दी योजना के अन्तर्गत दसवी कक्षा तक 7 लाख 9 हजार 497 विद्यार्थियों को दो जो़डे वर्दी प्रदान कर 52 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

7. मेरी सरकार ने 'राजीव गांधी डिजिटल छात्र योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरानस्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं तथा 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को 10 हजार लैपटॉप वितरित किए हैं। प्रदेश के 2 हजार 142 राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में मल्टी-मीडिया अध्यापन एवं आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों से लैस स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए गए हैं।

8. 'मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के विद्यार्थियों को भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये के ऋण पर 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

9. आदरणीय सदस्यगण मुझे इस सम्मानीय सदन को यह सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि प्रदेश के 99.88 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में पेयजल सुविधा, 99.79 प्रतिशत स्कूलों में छात्राओं के लिये अलग से शौचालय, 96 प्रतिशत स्कूलों में बिजली तथा लगभग 98 प्रतिशत स्कूलों में पुस्तकालयों की सुविधा प्रदान की गई है। हमारी उपलब्धियों को वर्ष 2016 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) में उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रदेश के विद्यार्थियों द्वारा अंक गणित अध्ययन में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया गया है। प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर स्कूल छोडने की प्रवृत्ति 1 प्रतिशत से कम है तथा 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों की पाठशाला में नामांकित होने की दर 99.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है जो कि देश में सबसे अधिक है। प्रदेश में 10 हजार 950 दिव्यांग छात्रों को स्कूल में दाखिल किया गया है ताकि उन्हें अन्य बच्चों के साथ समावेशित शिक्षा प्रदान की जा सके। 1 हजार 822 गम्भीर व अति गम्भीर दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षकों व 23 गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है।

10. वर्ष 2016-17 के दौरान अध्यापकों के 1 हजार 700 पद भरे गए तथा 2 हजार 500 अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया अन्तिम स्तर पर है। इसके

अतिरिक्त 959 पी0जी0टी0, 207 कॉलेज सहायक प्रवक्ता, 1 हजार 150 टी0जी0टी0, 342 जे0बी0टी0, 21 सी0 एण्ड वी0 अध्यापकों एवं 117 अनुबन्ध पर कार्यरत क्लर्कों को नियमित किया गया है। 2 हजार 349 प्राथमिक सहायक अध्यापकों एवं ग्रामीण विद्या उपासकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया गया है।

11. मेरी सरकार ने पी0जी0टी0 के पी0टी0ए0 अनुदान को 12 हजार 510 रूपये से ब़ढाकर 14 हजार 130 रुपये प्रतिमाह तथा सीएण्डवी अध्यापकों के पीटीए अनुदान को प्रथम अप्रैल, 2016 से 12 हजार 150 रुपये से ब़ढाकर 13 हजार 590 रुपये प्रति माह किया है। प्राथमिक सहायक अध्यापकों के मानदेय को 8 हजार 900 रुपये से ब़ढाकर 11 हजार रुपये प्रतिमाह तथा ग्रामीण विद्या उपासकों के मानदेय को 3 हजार 500 रुपये से ब़ढाकर 7 हजार रुपये किया है। अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1 हजार 700 रुपये से ब़ढाकर 1 हजार 900 रुपये प्रतिमाह किया गया है।

12. सरकार गत चार वर्षों के दौरान राज्य में केन्द्रीय वित्त पोषित चार संस्थानों सहित दो इंजीनियरिंग कालेज, एक फार्मेसी कॉलेज, पांच पॉलीटैक्निक, 10 अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित 34 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऑटोमोबाईल क्षेत्र में एक सामुदायिक कॉलेज स्थापित करने में सफल रही है।

13. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करने के लिए मेरी सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान 16 विशेषज्ञों सहित 155 चिकित्सकों, 426 स्टाफ नर्सों, 40 ऑपरेशन थियेटर सहायकों की नियुक्ति की है। इसके अलावा दंत चिकित्सकों के 50 पद तथा दंत मैकेनिकों के 50 पद सृजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत अभी तक विभिन्न श्रेणियों के 208 पद भरे गए हैं। मेरी सरकार ने इस वर्ष के दौरान 13 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक सिविल अस्पताल खोला है।

14. नाहन, हमीरपुर तथा चंबा में नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 115 करोड रुपये की धनराशि जारी की गई है। इस वर्ष से मेडिकल कॉलेज नाहन में प्रथम बैच आरम्भ कर दिया गया है।

15. प्रदेश सरकार ने नेरचौक मण्डी स्थित ई0एस0आई0 अस्पताल का अधिग्रहण कर इसका नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज रखा है। इस कॉलेज के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 732 पद सृजित किए गए हैं।

16. आई0जी0एम0सी0 शिमला तथा आर0पी0जी0 कॉलेज टाण्डा में आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से आवश्यक स्टॉफ सृजित कर आपातकालीन औषधी विभाग स्थापित किये गये हैं। शिमला

के समीप चमियाणा में भारत सरकार की पी0एम0एस0एस0वाई0 चरण-3 योजना के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण के प्रस्ताव को भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के दूसरे परिसर को स्थापित करने के लिए चमियाणा में 18 हैक्टेयर भूमि का चयन किया गया है।

17. चालू वित्त वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान शिमला, डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा तथा डा.यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए 11 करोड़ 81 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में स्नातकोत्तर की आठ सीटें ब़ढाई गई हैं।

18. मेरी सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 56 औषधियों तथा 10 उपभोज्य निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसके लिये 68 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

19. प्रदेश में पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम (पीसीएण्डपीएनडीटी एक्ट) लागू करने के लिये तथा लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए 270 अल्ट्रासांउड क्लीनिक पंजीकृत किए गए हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत ट्रायल कोर्ट में 6 अभियोग चल रहे हैं।

20. प्रदेश में स्वास्थ्य मानकों में बेहतर परिणाम सामने आए हैं। जन्मदर कम होकर राष्ट्रीय स्तर के 21 की तुलना में 16.4 तक पहुंच गई है। शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर के 42 के मुकावले 28 हो गई है जबकि कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.3 की तुलना में केवल1.7 है।

21. राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा 108 राज्य के लोगों को बेहतरीन एवं समयबध्द सेवाएं प्रदान कर रहीहै। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक 1 लाख 2 हजार 828 लोगों ने इस सेवा का लाभउठाया है।प्रदेश में संस्थागत प्रसव की दर 85 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

22. गैर संक्रमण रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में दिसम्बर, 2016 तक आठ लाख लोगों के मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की निःशुल्क जांच की गई है। आई0आर0डी0पी0 तथा बी0पी0एल0 परिवारों का प्रदेश में निःशुल्क दंत उपचार किया जा रहा है। 31.12.2016 तक 63 हजार 780 रोगियों का उपचार किया गया। 2 हजार 800 के लक्ष्य के मुकाबले लोगों को 2 हजार 838 डेंचर प्रदान किए गए हैं।

23. दिसम्बर, 2016 तक मोतियाबिंद के 16 हजार 72 ऑपरेशन किए गए हैं तथा 15 हजार 921 लेंस प्रत्यारोपित किए गए हैं। 576 बच्चों को निशुल्क चश्मे प्रदान किए गए हैं। राज्य के दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में 22 मल्टी स्पेशियलिटी शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किये गये।

24. प्रदेश में भांग की खेती के उन्मूलन के लिये मेरी सरकार ने राज्यभर से भांग को नष्ट करने के लिये अगस्त व सितम्बर, 2016 में एक विशेष अभियान चलाया और 2 हजार 145.75 हैक्टेयर भूमि से भांग के पौधों को नष्ट किया। युवाओं विशेषकर विद्यार्थियों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का दुरुपयोग रोकने के लिये राज्य में खुली सिगरेट व बीड़ी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

25. राज्य में आयुर्वेद विभाग का सुदृढीकरण किया जा रहा है। मेरी सरकार ने 38 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 बिस्तरों का एक आयुर्वेद अस्पताल खोला है और विभिन्न श्रेणियों के 115 नए पदों का सृजन किया है। इस वर्ष के दौरान 30 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

26. मेरी सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 40 पद तथा 91 अन्य पद भरे गये हैं। इसके अतिरिक्त, सह स्थान के अन्तर्गत रोगी कल्याण समिति के माध्यम से सहायक चिकित्सा अधिकारियों के 116 पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्ति की गई है तथा 100 दैनिक भोगी (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गई हैं।

27. प्रदेश में कुल 2.27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र फल उत्पादन के अधीन है जिसमें से इस वर्ष के दौरान 3 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को फल उत्पादन के अन्तर्गत लाया गया है।

28. प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान से फल उत्पादकों को क्षतिपूर्ति के लिए प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। अभी तक 1 लाख 493 किसानों तथा 71 लाख 22 हजार 283 फलदार वृक्षों का बीमा किया गया है तथा 25 प्रतिशत प्रीमियम उपदान के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा 9 करोड़ 13 लाख रुपये वहन किए गए हैं। योजना को सेब के लिए 36 खंडों में, आम के लिए 41 खंडो में, प्लम के लिए 13 खंडों में, आडू के लिए 5 खंडों में तथा नींबू प्रजाति फसलों के लिए 15 खंडों में इसे लागू किया गया है। सेब उत्पाद के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान 10 करोड 5 लाख रुपये मूल्यका 16 हजार 177.42 मीट्रिक टन 'सी' ग्रेड सेब मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदा गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत वर्ष 2016-17 में 4.34 मीट्रिक टन आम तथा नींबू प्रजाति के फलों की भी खरीद की गई।

29. सरकार उच्च मूल्य के पुष्प एवं सब्जी की संरक्षित खेती पर विशेष बल दे रही है। लगभग 95 हजार 169 वर्ग मीटर क्षेत्र को ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाऊस के अन्तर्गत लाया गया है। बागवानी फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए 15 लाख 51 हजार 813 वर्ग मीटर क्षेत्र को

एंटी हेलनेट तथा 659 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके लिए 4 हजार 395 मीट्रिक टन वर्मी कम्पोस्ट प्रतिवर्ष क्षमता की 517 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयां स्थापित की गई हैं। प्रदेश में 2.23 लाख उन्नत किस्म के सेब, नाशपाती, चेरी, आड़ू तथा प्लम के गुणात्मक रूट स्टॉक आयात किए गए। वर्ष के दौरान 500 हैक्टेयर क्षेत्र को ऐप्पल रिजूविनेशन परियोजना के अन्तर्गत लाया गया है।

30. हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना के तहत विश्व बैंक ने 1 हजार 134 करोड़ रुपये की कार्यान्वयन योजना स्वीकृत की है।

31. मेरी सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। प्रदेश की 69 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।

32. पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग के लिए प्रदेश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। किसानों को 3 लाख 89 हजार 301 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।

33. मेरी सरकार ने किसानों व कृषि कामगारों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना नामक नई योजना आरम्भ की है जिसका वे समुचित लाभ उठा रहे हैं।

34. डॉ0 वाई0 एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश में 2 हजार 525 पॉलीहाउस स्थापित किए गए हैं जिनका क्षेत्रफल 41.37 हैक्टेयर है। इस योजना पर 53 करोड़ 45 लाख रूपये व्यय किए गए है। मेरी सरकार ने 'उत्तम चारा उत्पादन योजना' के अन्तर्गत 20 हजार क्विंटल चारा बीज तथा 2 हजार 720 चारा काटने वाली मशीने 50 प्रतिशत उपदान पर वितरित की। किसान की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए सौर तथा बिजली की बा़डबंदी पर 60 प्रतिशत का उपदान दिया जा रहा है।

35. प्रदेश में जैविक खेती प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि केमिकल उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता को कम किया जा सके। लगभग 36 हजार किसानों ने प्रदेश में जैविक खेती को अपनाया है। प्रदेश सरकार ने अभी तक किसानों को 7 लाख 14 हजार 221 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए हैं।

36. प्रदेश में सिंचाई क्षमता में वृध्दि के लिए मेरी सरकार ने वर्ष 2016-17 में जल भंडारण टैंक, फलों स्कीम एण्ड वाटर केरिंग पाईप योजना आरम्भ की है। अभी तक लगभग 750 किसानों को आठ करो़ड रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इस वर्ष लगभग 76 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में 16.50 लाख मीट्रिक टन सब्जी उत्पादन हुआ है।

37. मेरी सरकार द्वारा पशुपालन क्षेत्र को सुदृढ किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के 266 पद भरे गए हैं। दो नये पॉलि-क्लीनिक, 26 पशु औषधालय तथा दो पशु अस्पताल खोले गए हैं। 34 पशु औषधालयों को पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत किया गया हैं। गुणात्मक कृत्रिम वीर्यारोपण सेवाएं सुनिश्चित बनाने के लिए घणाहट्टी और पालमपुर में 6 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से दो तरल नाईट्रोजन संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

38. आठ लाख भेड़-बकरियों को डिपिंग एवं ड्रेंचिंग सुविधाएं प्रदान करने पर 4 करोड़ 25 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के शाहपुर तथा किन्नौर जिला के सांगला में दो सचल भेड़ डिप टेंक स्थापित किए गए हैं।

39. राज्य में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गौ-वंश के संरक्षण, कल्याण एवं विकास के लिए गौ-वंश संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है। पशुओं के लिए नई प्रजनन नीति बनाई गई है। गैर सरकारी संगठनों को उनके द्वारा संचालित आवारा पशुओं के गौ-सदन के लिए भूसा-तूड़ी के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है।

40. मेरी सरकार ने प्रथम अप्रैल, 2016 से दूध के प्रापण मूल्य में एक रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। वर्ष 2016-17 में 1 हजार 321 हजार टन दुग्ध उत्पादन तथा 1 हजार 500 टन ऊन उत्पादन होने की संभावना है।

41. दिसम्बर, 2016 तक प्रदेश के सभी जलाशयों एवं जलस्त्रोतों से 81 करोड़ 19 लाख रुपये मूल्य की 7 हजार 712.50 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है। मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 13 हजार 413 मछुआरों एवं मत्स्य किसानों का बीमा किया गया है।

42. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश में 245 किलोमीटर वाहन योग्य स़डकें तथा 22 पुलों का निर्माण किया गया है। इस वर्ष के दौरान लगभग 40 गावों को सड़कों से ज़ोडा गया है।

43. नाबार्ड ऋण सहायता योजना के अंतर्गत 2 हजार 894 करोड 39 लाख रुपये की 1 हजार 166 विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर0आई0डी0एफ0) के अंतर्गत 1 हजार 718 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और दिसम्बर, 2016 तक 698 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। सरकार ने 570 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) धनराशि की व्यवस्था हेतु नाबार्ड को भेजी है।

44. चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिये आबंटित 350 करोड रुपये के विरुद्ध अभी तक 306 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं और दिसम्बर, 2016 तक 184 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

45. कुल 3 हजार 226 पंचायत मुख्यालयों में से 3 हजार 138 को 31 दिसम्बर, 2016 तक वाहन योग्य सड़क से जोड़ा जा चुका है। शेष 88 पंचायतों में से 74 पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है।

46. राज्य सडकों के रख-रखाव पर 218 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं तथा वर्ष 2016-17 के लिये सडक सुरक्षा के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

47. राज्य के लोगों को सुरक्षित पेजयल प्रदान करने के उद्देश्य से 53 हजार 604 बस्तियों में से 32 हजार 550 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर की दर से पानी की सुविधा उपलब्ध की गई है। शेष 21 हजार 54 बस्तियों में से चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 हजार 308 बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है तथा नवम्बर, 2016 तक 656 बस्तियों को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना पर 330 करोड़ 14 लाख रूपये खर्च किए जा रहे है।

48. मेरी सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में नवम्बर, 2016 तक 1 हजार 433 हैंडपम्पों की स्थापना की है।

49. जनसंख्या में वृद्धि के दृष्टिगत हमीरपुर, सरकाघाट, धर्मशाला, नगरोटा-बगवां, कांगड़ा, मण्डी, मनाली, कुल्लू, रामपुर जलापूर्ति योजनाओं का संवर्द्धन यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत, जबकि नाहन तथा बंजार जलापूर्ति योजनाओं का संवर्द्धन राज्य बजट के अन्तर्गत किया जा रहा है।

50. वर्ष 2016-17 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2016 तक 1 हजार 384.21 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबन्धन (सी0ए0डी0डब्ल्यू0एम0) के लिए 58 करोड़ 20 लाख रुपये का व्यय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में अन्य बा़ढ नियंत्रण परियोजनाओं पर 160 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।

51. 9 मैगावॉट की बरूआ जल विद्युत परियोजना तथा 65 मैगावॉट की काशंग स्टेज-एक जल विद्युत परियोजना प्रारम्भ होने से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 74 मैगावॉट अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो रही है।

52. मेरी सरकार ने घरेलु बिजली खपत में कमी लाने के उद्देश्य से 30 जनवरी, 2017 तक 71 लाख 47 हजार 428 एलईडी बल्ब वितरित कर 11 लाख 59 हजार 788 उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया है।

53. वर्ष के दौरान हिमऊर्जा ने सार्वजनिक उपयोग के लिए 14 हजार 216 सोलर फोटोवोल्टेक स्ट्रीट लाईटें, 1 हजार 810 सोलर फोटोवोल्टेक घरेलू लाईटें स्थापित की हैं और कुल 378 किलोवॉट क्षमता के 88 सोलर फोटोवोल्टेक पॉवर प्लांटस स्थापित किए हैं। कुल 7 हजार 500 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम भी लाभार्थियों को प्रदान किए गए हैं।

54. सड़क परिवहन प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार है। हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम बेड़े में 2 हजार 768 बसें प्रतिदिन लगभग 5 लाख 54 हजार किलोमीटर का सफर तय करती हैं।

55. कैंसर, रीढ़ की हड्डी की चोट, किडनी तथा डायलेसिस के रोगियों को एक अटेंडेंट सहित निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुविधा सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों तथा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को भी प्रदान की जा रही है।

56. एच0आर0टी0सी0 के बेड़े में 300 नई बसें शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त निगम 88 सुपर स्पेशिलिटी वाल्वो/स्केना एवं 20 लग्जरी वातानुकुलित बसें भी चला रहा है ताकि नागरिकों को आरामदेह परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। निगम ने 'सिल्वर कार्ड योजना' तथा 'सम्मान कार्ड योजना' आरम्भ की है जिनके तहत बस किराए में छूट दी जाती है। यात्रियों को उचित मूल्य पर गुणात्मक खाना

प्रदान करने के लिए हमीरपुर, धर्मशाला, पालमपुर, बिलासपुर, मंडी तथा ऊना में 'हिम अन्नपूर्णा' ढाबे आरम्भ किए हैं।

57. मेरी सरकार ने गोविंद सागर, चमेरा तथा कोल बांध जलाशयों में जल परिवहन के प्रोत्साहन की पहल की है तथा इसके लिए परामर्शियों की नियुक्ति की गई है।

58. ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, समुदाय सशक्तिकरण, मानव एवं अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास मेरी सरकार की प्राथमिकता है।

59. 'स्वच्छ भारत मिशन' योजना के अन्तर्गत मेरी सरकार ने मार्च 2017 तक 'स्वच्छ हिमाचल' का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 28 सितम्बर, 2016 से 20 अक्तूबर, 2016 तक ओ0डी0एफ0 तथा 'स्वच्छ पेयजल अभियान' का शुभारम्भ किया गया। प्रदेश को 28 अक्तूबर, 2016 को 'खुले में शौचमुक्त' राज्य घोषित किया गया है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 54 करोड़ 61 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

60. मनरेगा के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2016 तक 4 लाख 33 हजार 611 परिवारों को रोजगार प्रदान करने पर 358

करोड़ 59 लाख रुपये व्यय कर 161.44 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।

61. विभिन्न जलागम कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिसम्बर, 2016 तक 258 करोड 75 लाख रुपये के लक्ष्य के विरूध्द 98 हजार 604 हैक्टेयर भूमि के उपचार पर 219 करोड़ 95 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

62. प्रदेश के 12 खंडों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 3 हजार 280 महिला स्वयं सहायता समूह को सहायता के लिए प्रस्तावित किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना के अन्तर्गत लगभग 15 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

63. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 3 हजार 644, मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1 हजार 923 तथा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 846 आवासों का निर्माण किया जा रहा है।

64. मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर चार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। 14वें वित्तायोग अनुदान के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थानों को

270 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों के कुल 345 पद भरे गए हैं।

65. मेरी सरकार ने राज्य वित्तायोग अवार्ड के अंतर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को 99 करोड़ 45 लाख रुपये जारी किए हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण तथा लघु उद्यमों के लिये उपदानयुक्त ऋण सहायता प्रदान कर शहरी गरीबों पर 10 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

66. शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम शहरों के लिये जलापूर्ति, मल निकासी तथा 13 शहरों में शहरी अधोसंरचना नवीकरण से जुडी 406 करोड़ 54 लाख रुपये लागत की 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

67. मेरी सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को 14वें वित्तायोग अवार्ड के अंतर्गत 26 करोड़ 96 लाख रुपये का बुनियादी अनुदान जारी किया है। विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में मल निकासी के अंतर्गत 39 करोड़ रुपये ख़र्च किए जा रहे हैं।

68. शिमला तथा कुल्लू शहरों में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत) का क्रियान्वयन किया जा रहा है और भारत

सरकार द्वारा 101 करोड़ 33 लाख रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

69. धर्मशाला शहर में 2 हजार 109 करोड़ 69 लाख रुपये की परियोजना लागत से स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा 20 करोड़ 67 लाख रुपये के राज्यांश (10 प्रतिशत) सहित 186 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की जा चुकी है।

70. शहरी क्षेत्रों में पार्किंग निर्माण के लिये 10 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है। इसी प्रकार, 20 शहरी स्थानीय निकायों में पार्कों के निर्माण के लिये 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

71. सम्माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने समाज के उपेक्षित एवं कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है तथा उनके कल्याण के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं।

72. विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के लिए वार्षिक आय सीमा को समान रूप से 35 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। मेरी सरकार ने वर्ष के दौरान 3 लाख 89 हजार 168 लोगों, जिनमें 49 हजार 247 नये लाभार्थी हैं, को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान करने पर 357 करोड़ 69 लाख रुपये व्यय किए हैं।

73. मेरी सरकार वर्ष के दौरान अन्तरजातीय विवाह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग विधवाओं, परित्यक्ताओं, एकल महिला एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को आवास उपदान प्रदान करने पर 23 करोड़ 68 लाख रुपये खर्च कर रही है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतू 1 करोड़ 92 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है।

74. मेरी सरकार दिव्यांग बच्चों की ओर विशेष ध्यान दे रही है। इन बच्चों को प्रथम कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक जिसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि भी शामिल है, छात्रवृति प्रदान की जा रही है। इस पर वर्तमान वर्ष के दौरान 1 करोड़ 32 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं। सुंदरनगर में एक विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है जहां 58 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग बच्चों के लिए स्थापित संस्थानों के रख-रखाव पर 1 करोड़ 22 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

75. दिव्यांग बालिकाओं (दृष्टि एवं श्रवण बाधित) के लिए अलग से सुन्दरनगर में विद्यालय एवं गृह संचालित किया गया है, जिसके लिए 9 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से नये भवन का निर्माण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, ढली तथा धर्मशाला के दाड़ी में दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल चलाए जा रहे हैं।

76. मेरी सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 1 हजार 309 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

77. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछ़डा वर्ग, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों, एकल महिलाओं तथा बी0पी0एल0 परिवारों की विधवाओं को कौशल विकास के लिए 5 करोड़ 33 लाख रुपये के प्रावधान के साथ कंप्यूटर एवं सम्बद्ध गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

78. मेरी सरकार अधिसूचित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबध्द है। वित्त वर्ष के दौरान जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत 468 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है, जो कुल योजना आकार का 9 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के कल्पा, पूह तथा स्पीति सीमावर्ती खण्डों में 25 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।

79. मेरी सरकार ने राज्य के तीव्र तथा संतुलित औद्योगीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

80. 30-11-2016 तक राज्य में लगभग 2 लाख 90 हजार 228 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाली 20 हजार 170 करोड़ 11 लाख रुपये के कुल निवेश के साथ 42 हजार 745 पंजीकृत इकाइयां थी। सितम्बर, 2015 तथा नवम्बर, 2016 के बीच राज्य में 3 हजार 659 इकाइयों ने उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) फाईल किया है।

81. मेरी सरकार ने 17 दिसम्बर, 2016 को 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप/इनोवेशन mailto:vi नई औद्योगिक योजना आरम्भ की है। इस स्कीम के तहत स्टार्ट-अप उद्यमियों के लिए नई तरह के प्रोत्साहन का प्रावधान है।

82. पंडोगा तथा कंदरौरी में दो अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है और इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 28 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

83. अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य की नदियों के तटों पर खनिज-खदानों की नीलामी की जा रही है। वर्ष के दौरान अवैध खनन के 6 हजार 840 मामले सामने आए हैं, जिनमें 5 हजार 104 मामले कम्पाऊंड किए गए तथा 2 करोड़ 93 लाख रूपए का जुर्माना वसूल किया गया।

84. कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत 72 हजार 351 लाभार्थियों को 33 करोड़ 25 लाख रुपये वितरित किए गए। योजना के आरम्भ होने के उपरांत 31 दिसम्बर, 2016 तक 1 लाख 58 हजार 100 लाभार्थियों को 116 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

85. मेरी सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 18 लाख 26 हजार 250 राशन कार्ड धारकों को 3 लाख 68 हजार 958 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किए हैं।

86. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों को 35 किलो राशन प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के ए0पी0एल0 परिवारों को 20 किलो गेहूं का आटा तथा 15 किलो चावल तथा गैर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को 13 किलो गेहूं का आटा तथा 6 किलो चावल प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह वितरित किए जा रहे हैं।

87. मेरी सरकार सभी राशनकार्ड धारकों को विशेष 'राज्य उपदान योजना' के अन्तर्गत निर्धारित दर पर तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा एक किलो आयोडीन युक्त नमक प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसके अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक 210 करोड़ रुपये व्यय

किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के 10 जिलों में एल0पी0जी0 उपभोक्ताओं के लिए सीधा लाभ हस्तांतरण योजना को लागू किया है।

88. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता एवं समयबध्द उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए ई-पीडीएस परियोजना आरम्भ की गई है। अभी तक 16 लाख 64 हजार राशनकार्ड का डिजिटाईजेशन किया गया है।

89. मेरी सरकार राज्य में वन संसाधनों के संरक्षण, विकास तथा सतत प्रबन्धन के प्रति संवेदनशील है।

90. इस वित्त वर्ष के दौरान 14 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है। 700 हेक्टेयर क्षेत्र में मिट्टी तथा नमी संरक्षण गतिविधियां की जा रही हैं। 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र से लैंटाना तथा अन्य खरपतवारों को उखाड़ा जा रहा है। इस वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न वनीकरण गतिविधियों पर 200 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। वर्ष के दौरान 465 पद वन रक्षकों तथा 158 पद मल्टीपरपज कामगारों के भरे गए हैं।

91. मेरी सरकार के अथक प्रयासों से नगर निगम शिमला की सीमाओं तथा वन क्षेत्र के बाहर राज्य की 38 तहसीलों में बंदरों को वर्मिन घोषित किया गया है। 8 जनवरी, 2017 तक 1 लाख 18 हजार 17 बंदरों की

नसबंदी की गई है, जो राज्य में बंदरों की मौजूदा आबादी का लगभग आधा है।

92. जलवायु परिवर्तन की अतिसंवेदनशीलता में कमी लाने तथा ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण लघु एवं सीमान्त किसानों की अनुकूलक क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से सिरमौर जिला में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलक निधि के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान से एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

93. मेरी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को विशेष तरजीह दे रही है। सरकार ने परम वीर चक्र तथा अशोक चक्र वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों के अनुदान में 25 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तथा महावीर चक्र के लिये 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये की एकमुश्त ब़ढौतरी की है। इन पुरस्कार विजेताओं की वार्षिकी में भी वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, अन्य वीरता तथा सैन्य बलों के लिये विशिष्ट सेवा पुरस्कारों की वार्षिकी को भी दोगुना किया गया है।

94. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान हि.प्र. पूर्व सैनिक रो़जगार प्रकोष्ठ, हमीरपुर के माध्यम से 646 पूर्व सैनिकों और आश्रितों को राज्य/केन्द्रीय सेवाओं में रो़जगार प्रदान किया गया है।

95. बिलासपुर, हमीरपुर तथा सिरमौर जिलों में समेकित सहकारिता विकास परियोजना का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। कांग़डा, कुल्लू तथा शिमला जिलों में 81 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से तीन नई सहकारिता विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया गया है, जिनमें से प्रथम व द्वितीय वर्ष की 56 करोड़ 56 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

96. राज्य के सहकारी बैंकों ने सितम्बर, 2016 तक 359 करोड़ 46 लाख रुपये के फसल ऋण वितरित किए हैं।

97. मेरी सरकार राज्य में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। धर्मशाला, चामुण्डा, पलचान से रोहतांग तथा बिजली महादेव रज्जू मार्गों के विकास के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है।

98. राज्य में वर्ष 2016 (जनवरी से दिसम्बर) में सैलानियों की संख्या बढ़कर 184 लाख 50 हजार तक पहुंच गई है तथा पिछले वर्ष की तुलना में 5.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

99. राज्य सरकार पर्यटन इकाइयों के लिए पूंजी निवेश अनुदान पर 15 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है।

100. राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों में एशियन विकास बैंक वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत पर्यटन अधोसंरचना के सृजन पर 640 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

101. मेरी सरकार ने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। 386 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिनमें से 14 को चालू वित्त वर्ष के दौरान नियुक्तियां दी गई हैं। इस वर्ष के दौरान खेल अधोसंरचना विकास पर 22 करोड़ 90 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

102. अटल बिहारी वाजपेयी पवर्तारोहण एवं सम्बध्द खेल संस्थान मनाली द्वारा 31 दिसम्बर, 2016 तक विभिन्न साहसिक खेलों में 4 हजार 851 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

103. हिमाचल प्रदेश अपनी समृध्द सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। मेरी सरकार प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों के जीर्णोद्धार और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्मारकों के रखरखाव के लिए 1 करोड़ 79 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्रदेश भर में आयोजित होने

वाले विभिन्न मेलों के लिए 45 लाख 90 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कुल्लू, सोलन, मण्डी तथा ऊना में इंडोर सभागारों के निर्माण के लिए 29 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

104. प्रदेश में विभिन्न प्रेस क्लबों के निर्माण व इन क्लबों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 करोड़ 38 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

105. पर्यावरण मित्र गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये पर्यावरण मित्र विद्युत वाहनों को पांच वर्षों के लिये वैट में छूट दी गई है, सभी प्रकार की एलईडी लाईटों पर वैट कम करके 5 प्रतिशत किया गया है, एन्टी हेल नेटस् पर वैट 13.75 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है और औद्योगिक आयातों पर प्रवेश कर, मौजूदा औद्योगिक इकाईयों तथा नई औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य के बाहर से कच्चा माल व पैकिंग सामग्री लाने पर (मौजूदा औद्योगिक इकाईयों के लिये) क्रमशः 2 प्रतिशत से एक प्रतिशत तथा (नई औद्योगिक इकाईयों के लिये) एक प्रतिशत से आधा प्रतिशत किया गया है। रज्जू मार्गों तथा सिनेमा घरों में मनोरंजन कर मई, 2016 से मौजूदा 25 प्रतिशत व 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है।

106. मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से राजस्व मामलों में नीतियों व प्रक्रियाओं में सुधार आया है।

107. प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं व सीमेंट परियोजनाओं के लिए आदर्श पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना बनाई है। अब इस योजना के प्रावधानों के अनुरूप परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनःस्थापित किया जा रहा है।

108. मेरी सरकार ने 154 नए फील्ड काननूगो वृत्तों का सृजन किया है और कानूनगो के 154 अतिरिक्त पदों को भरा है और इतने ही चतुर्थ श्रेणी के पदों को भी भरा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 1 हजार 268 पदों जिसमे 1 हजार 120 पद पटवारियों के है, को भरने की स्वीकृति प्रदान की है।

109. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान राज्य आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के तहत उपायुक्तों तथा अन्य विभागों को ऐच्छिक राहत प्रदान करने, क्षतिग्रस्त अधोसंरचना की मुरम्मत एवं पुनर्निमाण के लिए 243 करोड़ 89 लाख रुपये की राशि जारी की है।

110. मेरी सरकार ने सरकारी सेवाओं की पहुंच आम आदमी तक सुनिश्चित बनाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के अन्तर्गत अनेक कदम उठाए हैं। सरकारी खरीद में ऑनलाईन निविदा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिसका वर्तमान में 22 विभागों, बोर्डों तथा निगमों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

111. डिजिटल इंडिया की शुरूआत तथा डिजिटल अदायगियों के बारे जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कॉमन सेवा केन्द्रों की टीमों ने ग्राम पंचायत, खण्ड तथा जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किए तथा 1 लाख 50 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

112. कार्य प्रणाली में ऑनलाईन व्यवस्था के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 1 हजार 800 से अधिक कार्यालयों को इंटरनेट सुविधा से जो़डा गया है।

113. नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए शिमला में कार पार्किंग, प्राथमिकी दर्ज करवाना तथा शिशु देखभाल संस्थानों के पंजीकरण व अनुश्रवण के लिए मोबाइल ऐप जैसी एप्लिकेशनज ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

114. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य द्वारा अनेक पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। मिड-डे-मील ऐप के लिए डिजिटल इंडिया गोल्ड अवार्ड-2016, सारथी-ऑनलाईन ड्राईविंग लाइसेंस सेवाएं परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड पुरस्कार, नागरिक सेवाओं को शासन प्रदान करने के लिए ई-जिला परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड पुरस्कार सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए कार्यों के कुछ साक्ष्य हैं।

115. मेरी सरकार ने समय-समय पर कर्मचारियों को अनेक वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर से अन्तरिम राहत प्रदान की है। सभी देय मंहगाई भत्ते की किश्तें जारी कर दी गई हैं। वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों तथा पेन्शन भोगियों को मंहगाई भत्ते पर 400 करोड़ रूपये तथा अंतरिम राहत पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

116. आउटसोर्सिज आधार पर तैनात कर्मचारियों के कल्याण के लिए महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छह दिनों का चिकित्सा अवकाश भी दिया जा रहा है। एक अप्रैल, 2016 से दिहा़डीदार कर्मियों की दिहा़डी को 180 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है। अंशकालिक की दिहाड़ी को 22 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति घंटा किया गया है।

117. वाटर गार्ड के मानदेय को 1 हजार 350 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 500 रुपये किया गया है। ग्राम पंचायत वैटनरी सहायकों के मानदेय को भी 5 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है।

118. सरकार ने शिक्षा विभाग में 31.3.2016 को आठ साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अंशकालीन जलवाहकों की सेवाओं को दैनिक भोगी कामगारों में बदला है। इसके अतिरिक्त, 30.9.2016 को पांच वर्ष का

सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मियों को भी नियमित किया गया है। सरकार ने 31.3.2016 तथा 30.9.2016 को सात वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक भोगी तथा कंटीजेंट पेड कर्मचारियों की सेवाओं को भी नियमित किया है। सरकार ने शहीदों के एक पात्र आश्रित को रोजगार प्रदान करने का निर्णय भी लिया है।

119. मेरी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वचनबध्द है। पिछडे क्षेत्रों में ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिए पिछडा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत 65 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

120. वर्ष 2016-17 के दौरान स्टेट इन्नोवेशन फण्ड से तीन प्रस्ताव को वित्त पोषण की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य इन्नोवेशन पुरस्कार योजना भी आरम्भ की गई है।

121. राज्य सरकार 63.1 किलोमीटर लम्बी भानुपल्ली-बिलासपुर- बैरी-ब्रॉडगेज रेललाईन की लागत का 25 प्रतिशत और 33.23 किलोमीटर लम्बी चंडीग़ढ-बद्दी ब्रॉडगेज रेललाईन की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए सहमत है। हिमाचल प्रदेश के भीतर प़डने वाली दोनों रेल लाईनों के भूमि की भू-अधिग्रहण प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान चंडीग़ढ-बद्दी रेल लाईन के लिये 45 करोड़ रुपये का राज्यांश भी जारी कर दिया है।

122. 'विकास में जन-सहयोग' योजना के अन्तर्गत 17 करोड़ 63 लाख रुपये और क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना (एसडीपी) के अन्तर्गत 53 करोड़ 13 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस वर्ष के दौरान विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के तहत खर्च की सीमा को ब़ढाकर एक करोड़ रुपये किया गया है तथा मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अन्तर्गत 5 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

123. वर्ष 2016 के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में रही। अभी तक सभी प्रकार के 17 हजार 249 मामले दर्ज किए गए हैं।

124. नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कुल्लू, शिमला तथा कांग़डा में तीन नार्कोटिक क्राईम कन्ट्रोल फिल्ड इकाईयां स्थापित की गई हैं। पुलिस ने इस वित्त वर्ष के दौरान 377.5 किलोग्राम चरस, 27 किलोग्राम अफीम तथा 607.6 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है।

125. ल़डकियों से छे़डछा़ड से निपटने के लिये पुलिस टीम ने निहत्थे मुकाबला करने के लिये 'सामर्थ' योजना के अंतर्गत 68 हजार 317 स्कूली छात्राओं को प्रशिक्षित किया है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिये 'संरक्षण योजना' भी आरम्भ की गई है। मेरी सरकार ने वर्ष 2016 के

दौरान 16 महिला उप निरीक्षकों, 1 हजार 200 सिपाहियों तथा 300 महिला सिपाहियों की नियुक्तियां की हैं।

126. मेरी सरकार प्रत्येक स्तर पर राज्य से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये प्रतिबध्द है तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' की नीति को अपनाया गया है। क्राईम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपने सभी 12 पुलिस स्टेशनों को कम्पयूटरीकृत किया है। वर्ष के दौरान भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध 35 मामले दर्ज किए हैं।

127. मेरी सरकार ने गृह रक्षकों के मानदेय को 350 रुपये से बढ़ाकर 571 रुपये प्रतिदिन किया है। इस उद्देश्य पर 118 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

128. सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 10 अग्निश्मन चौकियां अधिसूचित कर स्थापित भी कर दी गई हैं। सरकार ने आग बुझाने वाले तकनीकी कर्मचारियों के 70 पदों को सृजित किया है तथा रिक्तियों के विरुद्ध संचालन स्टॉफ के 100 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है।

129. माननीय सदस्यगण हिमाचल विधानसभा ने हमेशा ही प्रजातंत्र की शानदार परम्पराओं का अनुसरण किया है। मैं यहां सभी उपस्थितजनों से समाज के सभी वर्गों के लिए संतुलित, न्यायसंगत तथा बिना किसी

भेदभाव के विकास को सुनिश्चित करने के प्रयासों में मेरी सरकार को सहयोग देने की अपील करता हूं। इस लक्ष्य की दिशा में अपने प्रयासों को निर्देशित कर हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा इस माननीय सदन में वाद-विवाद, विचार-विमर्श तथा परिसंवाद बहुत उपयोगी होगें तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक सार्थक साबित होगें।

जय हिन्द।

राष्ट्रगान गाया गया।

01/03/2017/1230/MS/AG/1

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 12.30 बजे अपराह्न पुनः प्रारंभ हुई।

01/03/2017/1230/MS/AG/2

अध्यक्षः आज बारहवीं विधान सभा का चौदहवां सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है। इस बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि

सदन में माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी बात रखने का पूरा मौका दूं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप भी नियमों के अधीन रह कर समूचे प्रदेश के महत्वपूर्ण मामलों को उठाकर अपना योगदान देंगे और सदन के समय का भरपूर सदुपयोग करेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की जो गरिमा पूरे देश में बनी है उसे आप बनाए रखेंगे तथा सदन के संचालन में मुझे पूरा सहयोग देंगे।

मैंने हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली एवं अध्यक्ष के निदेश के नवम् संस्करण का मुद्रण करवाया है जो आपकी सुविधा हेतु online उपलब्ध है और इसकी एक-एक मुद्रित प्रति भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी।

अध्यक्ष श्री जे0एस0 द्वारा----

01.03.2017/1235/जेके/डी0सी/1

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

बुधवार 01 मार्च, 2017 1-शासकीय/विधायी कार्य
2-अनुपूरक बजट प्रथम एवं अंतिम किस्त वित्तीय वर्ष 2016-17- प्रस्तुतीकरण
वीरवार 02 मार्च, 2017 1- शासकीय/विधायी कार्य
2-अनुपूरक बजट प्रथम एवं अंतिम किस्त वित्तीय

वर्ष 2016-17ः

i. सामान्य चर्चा
ii. मांगों पर चर्चा एवं मतदान ; और
iii. विनियोग विधेयक-पुरःस्थापना, विचार-विमर्श एवं पारण।

शुक्रवार 03 मार्च, 2017 1-शासकीय/विधायी कार्य।

2-राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

01.03.2017/1235/जेके/डी0सी/2

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएगें

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरांत महामहिम् राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिवः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

1. हेमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना संशोधन) विधेयक 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 1);
2. हेमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के वेश पर कर (द्वितीय संशोधन) वेधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 2); और

3.	हेमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 2017 का अधिनियम संख्यांक 3

01.03.2017/1235/जेके/डी0सी/3

अध्यादेश

अध्यक्षः अब अध्यादेश होगा। अब श्री कौल सिंह जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 31.01.2017 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 31.01.2017 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखता हूं।

01.03.2017/1235/जेके/डी0सी/4

अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2016-2017 का प्रस्तुतीकरणः

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अन्तिम किस्त को प्रस्तुत करेंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

01.03.2017/1240/SS-AG/1

मुख्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2016-17 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम तथा अन्तिम किश्त प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह अनुपूरक अनुदान मांगें कुल 3936 करोड़ 55 लाख रुपये की हैं, जिनमें से 2304 करोड़ 83 लाख रुपये गैर-योजना स्कीमों, 502 करोड़ 78 लाख रुपये योजना तथा 1128 करोड़ 94 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु प्रावधित किये गये हैं।

गैर-योजना व्यय में मुख्यतः 1660 करोड़ 39 लाख रुपये ऋणों/अर्थोपाय अग्रिम की वापसी, 160 करोड़ 91 लाख रुपये पुलिस व इससे सम्बद्ध संगठन, 149 करोड़ 03 लाख रुपये विभिन्न जलापूर्ति स्कीमों के लिए विद्युत प्रभार, 108 करोड़ 74 लाख रुपये एस0जे0वी0एन0एल0 को जैनरेशन टैरिफ के भुगतान और एच0पी0पी0सी0एल0 को ऋण उपलब्ध करवाने, 46 करोड़ 27 लाख रुपये सड़कों के निर्माण के लिए मुआवजे के भुगतान, 39 करोड़ 40 लाख रुपये भाषा, संस्कृति एवं जन सम्पर्क और 13 करोड़ 60 लाख रुपये न्याय प्रशासन के लिए प्रावधित किए गए हैं।

योजना स्कीमों के अन्तर्गत मुख्यतः 108 करोड़ 60 लाख रुपये विभिन्न सड़कों, भवनों व पुलों के निर्माण, 69 करोड़ 16 लाख रुपये भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन व विकास में जन सहयोग, 44 करोड़ 14 लाख रुपये नाबार्ड व एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों, 34 करोड़ 52 लाख रुपये नए मेडिकल कॉलेज भवनों व आई0जी0एम0सी0 में नए ओ0पी0डी0 ब्लॉक के निर्माण, 30 करोड़ 47 लाख रुपये स्मार्ट सिटी मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के लिए और 11 करोड़ 55 लाख रुपये अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत विकासात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए प्रावधित किए गए हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, इसमें से अधिकतर राशि चालू व नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केन्द्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धन राशि प्राप्त हुई, के

लिए प्रस्तावित है। 446 करोड़ 96 लाख रुपये रेणुका बांध विस्थापितों को मुआवजा, 187 करोड़ 33 लाख रुपये स्मार्ट सिटी मिशन, 172 करोड़ 98 लाख रुपये मेडिकल कॉलेज भवनों के निर्माण, 93 करोड़ 46 लाख रुपये शहरी अवसंरचना विकास योजना, 81 करोड़ 64 लाख रुपये आपदा प्रबन्धन,

जारी श्रीमती के0एस0

1.03.2017/1245/केएस/एजी/1
मुख्य मंत्री जारी-----

45 करोड़ रुपये केन्द्रीय सड़क निधि अनुदान के अंतर्गत सड़कों के निर्माण, 8 करोड़ 66 लाख रु0 आई0सी0डी0एस0, आई0सी0पी0एस0 व सबला, 8 करोड़ 49 लाख रुपये सभी के लिए आवास और 8 करोड़ 01 लाख रुपये न्यायिक अवसंरचना के उन्नयन के लिए प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुपूरक अनुदान मांगों की रूप रेखा प्रस्तुत की है। मांगों का पूरा विवरण माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से इन अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

"जय हिन्द"
"जय हिमाचल"।

****

1.03.2017/1245/केएस/एजी/2

अध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक वीरवार, 2 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 01 मार्च, 2017 **सचिव ।**